मुंबई का असली प्रतिनिधि कौन, ठाकरे बंधु या भाजपा?

इसी सवाल पर केन्द्रित है, बीएमसी चुनाव

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जनवरी। महाराष्ट्र में मुंबई और अन्य नगर निगम चुनावों के लिए प्रचार समाप्त होने के साथ ही, मुंबई एक बार फिर पहचान और प्रतिनिधित्व को लेकर तीखी राजनीतिक बहस के केन्द्र में आ गई है।

जहाँ शहर की सड़कों पर इसकी बहुलतावादी और बहुसांस्कृतिक पहचान झलकती है, लोहड़ी, पोंगल और उगादी जैसे त्योहार जोशो-खरोश के साथ मनाये जा रहे हैं, वहीं, राजनीतिक चर्चा ने चुनाव को इस सवाल में बदल दिया है कि "असली मुंबईकर" और मराठी मानुस का प्रतिनिधि कौन है। नागरिक मुद्दों पर हावी होती पहचान की राजनीति के चलते, यह मुकाबला भारत के इस सर्वाधिक विविधतापूर्ण महानगर में पहचान पर एक जनमत संग्रह जैसा बन गया है।

मतदान में 48 घंटे से भी कम समय शेष रहने के साथ, मुंबई देश की सबसे अमीर स्थानीय निकाय, "बृहन्मुंबई महानगरपालिका", के नियंत्रण को लेकर एक बेहद अहम राजनीतिक संघर्ष का केन्द्र बन गई है।

- ठाकरे बंधु और मु.मंत्री फड़नवीस के लिए अस्तित्व का प्रश्न बन गए हैं, बीएमसी चुनाव और दोनों पक्षों ने पूरी ताकत झोंक दी है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला भाजपा-नीत महायुति गठबंधन ठाकरे चचेरे भाइयों,उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे,के खिलाफ कड़े मुकाबले में है, जबकि पवार परिवार भी इस राजनीतिक रणभूमि में मौजूद है।

राजनीतिक अस्तित्व, मराठी पहचान, हिंदुत्व और शासन- प्रशासन को लेकर तीखे हमलों के बीच मुफ्त सुविधाओं, कल्याणकारी सहायता और नागरिक ढांचे में सुधार के वादे करने वाले घोषणापत्र चर्चा के केन्द्र में आ गए हैं। प्रचार के अंतिम घंटों में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि मुंबई के इस नागरिक निकाय की तिजोरी की चाबी किसके पास रहे, इसका फैसला पहचान की राजनीति करेगी या सुशासन के वादे।

ऊटी जाते समय मैसुर एयरपोर्ट पर डीके शिवकुमार से मिले राहुल

राहुल ने डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 जनवरी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, दोनों से दिल्ली आने को कहा है, ताकि मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाया जा सके। हालांकि, उनकी दिल्ली यात्रा की कोई तारीख अभी तय नहीं हुई है।

मंगलवार को कर्नाटक में मौजूद राहुल गांधी के समक्ष दोनों नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया और अटकलों को खत्म करने के लिए हाईकमान की योजनाओं पर स्पष्टता मांगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में फेरबदल का मुद्दा भी उठाया।

राहुल गांधी मंगलवार को पोंगल से पहले एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु में ऊटी जाते समय मैसूर पहुँचे थे।

दिल्ली लौटते समय, शिवकुमार उन्हें हवाई अड्डे पर विदा करने पहुँचे। हवाई अड्डे पर शिवकुमार, जो राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, और गांधी के बीच हुई बातचीत के विज़ुअल सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज़ हो गई।

शिवकुमार के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, लोकसभा

- एयरपोर्ट पर हुई इस मुलाकात ने कर्नाटक की राजनीति में हलचल मचा दी है और एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं।

में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार शाम मैसूर हवाई अड्डे पर उपमुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार के साथ चर्चा की। यह मीटिंग राहुल गांधी के तमिलनाडु से मैसूर पहुँचने और दिल्ली रवाना होने के बीच हुई।

शिवकुमार ने मीडिया से कहा, "मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हूँ और वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। हम जो भी चर्चा करते हैं, वह सब कुछ आपको नहीं बता सकते। आप लोग बेवजह यह अटकलें लगाकर मुद्दे बना रहे हैं कि क्या बात हुई। उनकी ओर से कोई संदेश नहीं था। उन्होंने हमें अच्छा काम करने को कहा। हमने उन्हें मनरेगा और इसे आगे ले जाने की हमारी योजना के बारे में बताया।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब ऐसी अफ़वाहें जोरों पर हैं कि कांग्रेस हाईकमान संक्रांति के बाद नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा के लिए दोनों नेताओं को दिल्ली बुला सकता है।

इस बीच, सिद्धारमैया ने मीडिया से कहा कि पार्टी में कोई उलझन नहीं है। उन्होंने कहा, कौन-सी अटकलें? ये सिर्फ मीडिया की अटकलें हैं। आप ही लोग अटकलें पैदा कर रहे हैं। ऐसे सवाल उठाना ही निराधार है। पार्टी में परेशानी कहाँ है? ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं है।"

लेकिन सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री का खेमा इन घटनाक्रमों पर बारीक नज़र बनाए हुए है।

यह सारी खींचतान 2023 के चुनाव परिणाम के समय से चली आ रही है, जिसमें कांग्रेस ने ज़बरदस्त जीत दर्ज की थी।

उस समय राज्य में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाने के कारण शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। अंततः कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें उपमुख्यमंत्री और राज्य पार्टी अध्यक्ष पद स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। उस समय कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया था कि रोटेशनल मुख्यमंत्री व्यवस्था पर सहमति बनी है, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई।

फतहपुर में ट्रक-कार भिड़ंत में एक परिवार की 6 महिलाओं की मौत

वे लक्ष्मणगढ़ में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लौट रही थीं

सीकर, 14 जनवरी (निसं)। सीकर में ट्रक और कार की भीषण भिड़ंत में छह महिलाओं की मौत हो गई तथा तीन लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। हादसा जयपुर-बीकानेर हाईवे पर फतेहपुर के हरसवा गांव के पास बुधवार शाम चार बजे हुआ। हादसे में अर्टिगा कार चकनाचूर हो गई। कार में सवार लोग उसमें फंस गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने शव और घायलों को बाहर निकाला। घायलों को फतेहपुर के ट्रॉमा सेंटर लाया गया। किन्तु हालत गंभीर होने के कारण, उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कार में सवार लोग अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे

डीएसपी अरविंद कुमार जाट ने बताया कि फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र में अर्टिगा कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई। मोड़ पर कार कंट्रोल नहीं हो सकी और सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की मदद से रास्ते से हटाकर ट्रैफिक को सुचारू करवाया गया। थाना अधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि अर्टिगा कार में सवार लोग लक्ष्मणगढ़ (सीकर) से फतेहपुर अपने घर लौट रहे थे। ट्रक सीकर की ओर जा रहा था। हादसे में संतोष पत्नी सत्यनारायण, तुलसी देवी पत्नी ललित, मोहनी देवी

- जयपुर-बीकानेर हाईवे पर अर्टिका कार चकनाचूर हो गई।

पत्नी महेश कुमार, इंद्रा पुत्री महेश कुमार, आशा पत्नी मुरारी और चंदा पत्नी सुरेन्द्र की मौत हो गई। घायल सोनू, वसीम और बरखा को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया है। मृतकों के परिवार के सदस्य ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ में रहने वाली हमारी बुआ का निधन हो गया था। परिवार के लोग सुबह 11 बजे पांच गाड़ियों में सवार होकर उनके अंतिम संस्कार में गए थे। दोपहर 3ऑ :30 बजे परिवार के सभी लोग वहाँ से निकले थे। इस दौरान अर्टिगा कार का एक्सीडेंट हो गया।

प्र.मंत्री मोदी आज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तंत्र में काम करने वाले लोगों के परस्पर संवाद के तरीके को बदलने और पुराने भवन के साथ जुड़ी औपचारिकताओं की परतों को कम करने के लिए बनाया गया है।

जहाँ साउथ ब्लॉक में औपनिवेशिक स्थापत्यकला की छाप थी, वहीं सेवा तीर्थ में आधुनिक डिज़ाइन एवं भारतीय सभ्यतागत तत्वों का संगम है।

इसके आंतरिक हिस्सों में भारत की विरासत से प्रेरित सांस्कृतिक चित्र दिखाई देते हैं, लेकिन सारे डिज़ाइन में ज्यादा तामझाम नहीं है और सुगम कार्य व्यवस्था को तवज्जो दी गई है।

प्रधानमंत्री के निजी और औपचारिक बैठक कक्षों को इस तरह पुनःडिज़ाइन किया गया है कि वे विदेशी नेताओं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों की मेज़बानी परंपरा और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के संगम वाले परिवेश में कर सकें।

राष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राष्ट्रपति के इस दौरे से आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के साथ-साथ राजस्थान के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

अब 55 देशों में वीज़ा के बिना एंट्री मिलेगी भारतीयों को

नई दिल्ली, 14 जनवरी। हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी 2026 की नवीनतम पासपोर्ट रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया है और पिछले एक साल में भारत ने अपनी स्थिति में 5 स्थानों का सुधार करते हुए 85वें स्थान से 80वें स्थान पर छलांग लगाई है। यह प्रगति भारतीय नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा के अवसरों में वृद्धि का संकेत देती है, हालांकि वीजा-फ्री एक्सेस वाले देशों की संख्या में मामूली कमी आई है।

वर्ष 2026 की रैंकिंग के अनुसार,

- भारत अब 85वें से 80वें स्थान पर आ गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट रैंकिंग में टॉप पर सिंगापुर हैं तथा दूसरा स्थान जापान व दक्षिण कोरिया का है।

भारतीय पासपोर्ट धारक अब दुनिया भर के 55 देशों में बिना पूर्व वीजा के या वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। वर्ष 2025 में, भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर था और 57 देशों में वीज़ा-फ्री पहुंच प्रदान करता था। 2024 में भी भारत की रैंक 80 थी, जिसका अर्थ है कि 2025 में गिरावट के बाद 2026 में फिर से सुधार देखने को मिला है। हालांकि, वीज़ा-फ्री यात्रा वाले देशों की संख्या में 2 देशों की कमी आई है, जो एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में सिंगापुर ने लगातार दूसरे साल अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जो अपने धारकों, को 227 में से 192 देशों में वीजा-फ्री एंट्री की अनुमति देता है। यह सिंगापुर के मजबूत अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति का प्रमाण है। जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।

रैंकिंग के निचले सिरे पर, अफगानिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट बना हुआ है, जो सूची में सबसे नीचे 101वें स्थान पर है।

आईएनएसवी कौडिन्य जहाज मस्कट पहुँचा

मस्कट, 14 जनवरी। भारतीय नौसेना के प्राचीन पाल विधि से निर्मित जहाज आईएनएसवी कौंडिन्य ने ऐतिहासिक 18 दिनों की यात्रा पूरी कर ली है। यह जहाज 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से रवाना हुआ था और बुधवार को ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच गया। यह यात्रा भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं को जीवंत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों का सम्मेलन आज

नयी दिल्ली, 14 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को यहां संसद भवन परिसर के संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे और इसमें दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के 42 राष्ट्रमंडल देशों और 4 अर्ध-स्वायत्त संसदों के 61 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। यह सम्मेलन कई समकालीन

- सम्मलेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे।

संसदीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करेगा, जिसमें मजबूत लोकतांत्रिक संस्थानों को बनाए रखने में स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, संसदीय कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, सांसदों पर सोशल मीडिया का प्रभाव, संसद के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए नई रणनीतियाँ और मतदान से परे नागरिकों की भागीदारी, जैसे विषय शामिल हैं।

भारतीयों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

9891281091 15, 9891281091 09, 989128109102 और 989932179359 पर संपर्क कर सकते हैं। भारतीय दूतावास से ई मेल ... पर भी संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने सभी नागरिकों को बिना देरी के दूतावास में पंजीकरण कराने की सलाह दी है।

चीन ने 2025 में 1.2 ट्रिलियन डॉलर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को काबू में किया जा सके। लेकिन ट्रम्प की योजना के मुताबिक कुछ भी काम होता नहीं दिख रहा है।

यह सही है कि चीनी कस्टम्स के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका को होने वाला चीन का निर्यात लगभग 20 प्रतिशत घटा है। लेकिन इसके साथ ही यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे कई दूसरे देशों को उसका निर्यात बढ़ गया है, खास तौर पर इलेक्ट्रिक कारों और तकनीक आधारित उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ा है।

इस हफ्ते बीजिंग में चीनी व्यापार अधिकारियों की ब्रीफिंग के अनुसार, हाई-टेक वस्तुओं, जिनमें उन्नत मशीन टूल्स और औद्योगिक रोबोट शामिल हैं, का निर्यात सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों, लीथियम बैटरियों और फोटोवोल्टाइक उत्पादों (जैसे सोलर पैनल) का निर्यात 27 प्रतिशत बढ़ा है।

चीनी सफलता का मूल मंत्र यह है कि अपने उत्पाद किसी भी कीमत पर दुनिया भर के बाजारों में उतारो। चीनी निर्माता लागत के आधार पर कीमत तय नहीं करते, बल्कि इस आधार पर कीमत रखते हैं कि सामान बिक सके। यह क्लासिक मर्केंटिलिस्ट सिद्धांत है, जो काम कर रहा है।

मर्केंटिलिस्ट विचारक देश की आर्थिक नीति में बेहद कठोर रुख के लिए जाने जाते थे। इसे "अपने पड़ोसी को कमजोर करो" जैसी रणनीति कहा जा सकता है।

जब से चीन ने उस समय अमेरिकियों की मदद से ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में एंट्री की है, तब से चीन ने लगातार मुक्त बाजार व्यवस्था (फ्री मार्केट इकॉनमी) का पूरा फायदा उठाया। लेकिन उसके अपने काम करने के तरीके बने रहे। चीनी निर्माताओं के लिए मुनाफा उतना जरूरी नहीं होता, जितना कि बिक्री और बड़े पैमाने पर उत्पादन।

लगभग दो दशक पहले इस संवाददाता ने चीन जाकर वहां के उद्योगों को नजदीक से देखा था। उस समय चीन

- अपना माल विश्व भर में पहुँचाने के बाद चीन ने "रेअर अर्थ" खनिज को परिष्कृत करने की टैक्नॉलजी पर ध्यान लगाया। वर्षों बाद इस टैक्नॉलजी पर चीन का आधिपत्य व एकाधिकार हो गया है।
- पर, चीन की इस औद्योगिक नीति में एक कमी है, वह निर्यात पर आधारित है। अतः चीन की "डॉमैस्टिक डिमांड" बहुत कम है।

का निर्यात आज जितना हर जगह मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी नींव रखी जा रही थी।

चीनी औद्योगिक प्रबंधकों से बातचीत में पता चला कि जिला और प्रांतीय प्रशासन निर्यात के वादों के आधार पर उद्योगों को जमीन देते थे। बैंकों के ब्याज दर भी इस तरह तय होते थे कि उत्पाद विदेशों में बिक सकें। अगर कोई इकाई अपने निर्यात वादों को पूरा नहीं करती थी तो उस पर सख्त सवाल और सुधारात्मक कदम उठाए जाते थे।

डब्ल्यूटीओ में प्रवेश से चीनी उद्योगों को "मोस्ट फेवर्ड नेशन" का दर्जा मिला और उन्हें न्यूनतम टैरिफ का लाभ मिला। लेकिन चीन ने अपने बाजार में विदेशों से आने वाले उत्पादों पर कई तरह के बैन लगा रखे थे, जैसे - कुछ खास सामान के लिए तय बंदरगाह, हर आयातित वस्तु पर चीनी भाषा में लेबल की अनिवार्यता और चीनी मानकों का पालन।

आज चीन ने ऐसी आपूर्ति शृंखलाएं और उद्योग विकसित कर लिए हैं, जो उसके व्यापार साझेदारों की कमजोरियों का पूरा फायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए भारत की दवा इंडस्ट्री को देखें, जो दवाओं के कच्चे माल, यानी एपीआई के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है।

चीन ने दुर्लभ खनिजों के उत्पादन में भी जबरदस्त दूरदर्शिता दिखाई है। ये खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरणों से लेकर कार बैटरियों तक में जरूरी होते हैं। इनका उत्पादन चीन ने दशकों तक अपने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाकर बढ़ाया है।

इसमें कोई शक नहीं कि भारी कीमत चुकाकर, चीन अब दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की सप्लाई पर इतना मजबूत कब्जा करने में कामयाब हो गया है कि ट्रंप से टैरिफ युद्ध के दौरान, चीन अमेरिका के हाथ मरोड़ने की ताकत रखता था। चीन ने खनिजों की आपूर्ति पर पूरी तरह रोक लगाने की घोषणा कर दी, जिससे ट्रम्प को झुककर कम टैरिफ के साथ बातचीत के लिए वापस आना पड़ा।

समय-समय पर चीन उन देशों को भी आपूर्ति पर नियंत्रण लगाने की कोशिश करता है, जो उसके आर्थिक हितों के खिलाफ जाते हैं। उदाहरण के लिए, चीन ने भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स वाले प्रॉडक्ट्स के एक्स्पोर्ट पर भी इसी तरह की रोक लगाई थी, इस शर्त पर कि इन प्रॉडक्ट्स या इनपुट्स का इस्तेमाल करने वाले प्रॉडक्ट्स को यू.एस. सहित दूसरे देशों में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह विशाल व्यापार प्रदर्शन तब तक अच्छा है, जब तक चलता है, लेकिन यह चीन की नीति की गहरी कमजोरियों को भी उजागर करता है। चीन अब अपने सामान को विदेशों में बेचने पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया है। उसकी उत्पादन क्षमता घरेलू मांग से कहीं ज्यादा है।

घरेलू मांग कमजोर है और बड़े पैमाने पर बने मकान बिक नहीं पा रहे हैं। कई शहरों में अधूरे और खाली मकानों की भरमार है, जिन्हें 'घोस्ट टाउन' कहा जा रहा है। इनसे मकानों के दाम गिर रहे हैं और जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है, उनकी संपत्ति का मूल्य घट रहा है। कुल मिलाकर घरेलू मांग कमजोर बनी हुई है। चीन के आक्रामक निर्यात से उसके व्यापार साझेदार डर रहे हैं और भविष्य अनिश्चित नजर आ रहा है। हर चमकती चीज हमेशा सोना नहीं होती।

राजनीतिक लाभ ...

- वरिष्ठ कांग्रेस नेता हेमाराम चौधरी गत 3 जनवरी से पंचायत समितियों को तोड़कर गुड़ामलानी व धोरीमन्ना को बालोतरा जिले में शामिल करने के खिलाफ धरना दे रहे थे। उनके समर्थन में आयोजित आक्रोश रैली में पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा व विधायक दल के नेता टीका राम जूली ने भी भाग लिया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विधानसभा क्षेत्र गुड़ामालानी की पंचायत समितियों को तोड़कर गुड़ामालानी व धोरीमन्ना को बालोतरा जिले में शामिल करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी के नेतृत्व में 3 जनवरी से धोरीमन्ना उपखण्ड मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है। बुधवार को हेमाराम चौधरी द्वारा दिये जा रहे धरने का समर्थन करने एवं जन आकोश रैली के आगाज पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, रूपाराम धनदे, जैसलमेर, सांचौर के सुखराम बिश्नोई, पोकरण के साले मोहम्मद, विधायक हरीश चौधरी,पदमाराम मेघवाल, फतह खान, गफूर अहमद,रतन देवासी, सिमरजीत सिंह सहित कई जनों ने भाग लिया।

कांग्रेसजनों ने भारी संख्या में भीड़ के साथ उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन दिया। वरिष्ठ नेताओं की ओर से हेमाराम चौधरी को धरना समाप्त करने की बात कहने पर हेमाराम चौधरी ने कहा कि यह धरना मेरा नहीं था, पूरी क्षेत्र की जनता का है, उन सभी की बात सुनकर धरना समाप्त किया जाएगा।

सऊदी-अरब-पाकिस्तान-टर्की एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके अलावा, यह पाकिस्तान को ऐसे समय में रक्षा कवच दे सकता है, जब भारत-पाकिस्तान तनाव बना हुआ है। इस व्यवस्था को किसी एकल संधि के रूप में नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए।

व्यापक स्तर पर, सऊदी अरब-पाकिस्तान-तुर्की की यह बातचीत रणनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजरती दुनिया को दर्शाती है। जैसे-जैसे अमेरिका की सुरक्षा गारंटियाँ अधिक चयनात्मक हो रही हैं और इज़रायल व अमेरिकी हितों पर केन्द्रित हो रही हैं, वैसे-वैसे मध्यम दर्जे की शक्तियाँ वैकल्पिक या समानांतर सुरक्षा व्यवस्थाओं की तलाश कर रही हैं। सऊदी अरब के लिए यह वॉशिंगटन पर निर्भरता से आगे बढ़ने और विविधता लाने का प्रयास है। तुर्की के लिए यह राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन की इस्लामी दुनिया में अंकारा के प्रभाव का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है। पाकिस्तान के लिए इसके पक्ष में दलील ज्यादा तत्कालिक है, इससे उसे कूटनीतिक अलगाव से निकलने और भारत के साथ बार-बार हुए सैन्य टकरावों के बाद प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।

भारत की मुख्य चिंता इस उभरते त्रिकोण में पाकिस्तान की स्थिति को

- भारत की सामरिक रणनीति अब तीव्र गति से, सीमित दंडात्मक कार्यवाही पर निर्भर है, जैसा कि 2019 के बालाकोट हवाई हमले व मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया था। पर, "इस्लामिक नाटो" के नए घटनाक्रम ने भारत-पाक संघर्षों में एक अनिश्चितता का तत्व मिला दिया है, जिससे अब यह कहना, कि भविष्य में भारत-पाक युद्ध द्विपक्षीय मामले रहेंगे, मुश्किल है।

लेकर है। इस्लामाबाद पहले से ही चीन के मजबूत रणनीतिक समर्थन का लाभ पा रहा है। अब सऊदी अरब और तर्की के जुड़ने से एक राजनीतिक और सैन्य क्षमता बढ़ जाती है, जो संकट के समय पाकिस्तान को अधिक आत्मविश्वासी बना सकता है। भले ही ये वार्ताएँ किसी बाध्यकारी पारस्परिक रक्षा संधि तक न पहुँचें, लेकिन नाटो-शैली की भाषा, जहाँ "किसी भी हमले" पर सामूहिक प्रतिक्रिया की बात होती है, का प्रयोग अपने आप में स्पष्ट प्रतिरोधक मूल्य रखता है।

यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का सैन्य सिद्धांत अब परमाणु हमले से कुछ नीचे, किंतु तेज़, सीमित और दंडात्मक कार्रवाई पर अधिक निर्भर करता है, जैसा कि 2019 के बालाकोट हवाई हमलों और मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया। कोई भी ऐसा ढाँचा, जो इस अनिश्चितता को बढ़ा दे कि भविष्य का भारत-पाकिस्तान टकराव पूरी तरह द्विपक्षीय ही रहेगा या नहीं, भारत की आक्रामक गणना को जटिल बनाता है और कार्रवाई की कूटनीतिक लागत को भी बढ़ाता है।

तुर्की की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तुर्की, कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाज़ी ही नहीं कर रहा है, वह नाटो का दीर्घकालिक सदस्य है, जिसके पास उन्नत और तेज़ी से बढ़ता रक्षा उद्योग, ड्रोन युद्ध का व्यापक अनुभव और वैश्विक हथियार आपूर्तिकर्ता बनने की महत्वाकांक्षा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की का खुला राजनीतिक समर्थन था और खबर है कि वह उसे सैन्य समर्थन भी दे रहा था और भारत के साथ टकराव की स्थिति और नाटो के दृष्टिकोण से असहज रूप से तुर्की को इस्लामाबाद के करीब ले आई हैं।

यदि तुर्की पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक रूप से जुड़ जाता है, तो पाकिस्तान की सैन्य क्षमता में लगातार वृद्धि होगी, ड्रोन और नौसैनिक प्लेटफॉर्म से लेकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तक, और संभवतः तुर्की के पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान तक पाकिस्तान की अगली पीढ़ी पहुँच बढ़ जाएगी। दक्षिण एशिया के सूक्ष्म रूप से संतुलित सैन्य वातावरण में, ऐसे छोटे-छोटे बदलाव भी रणनीतिक रूप से बड़े प्रभाव डाल सकते हैं।

सऊदी अरब की भूमिका अपेक्षाकृत शांत है, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। रियाद ने परंपरागत रूप से पाकिस्तान के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को भारत के साथ लगातार गहराते आर्थिक और रणनीतिक साझेपन के साथ संतुलित किया है। हालांकि, पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को ध्यान में रखने वाली किसी सुरक्षा व्यवस्था को समर्थन देना सऊदी-पाकिस्तान संबंधों के आंशिक स्तर पर पुनः राजनीतिकरण का संकेत हो सकता है। फिर भी, यह संभावना कम है कि रियाद भारत के साथ एक बड़े ऊर्जा खरीदार और निवेश स्थल के रूप में बढ़ते संबंध को खतरे में डाले। सऊदी भागीदारी संभवतः भारत का सामना करने की किसी मंशा से अधिक, ईरान को लेकर चिंताओं और अमेरिका की आंशिक वापसी से प्रेरित है।

फिर भी, संकट के समय धारणाएँ मायने रखती हैं। रणनीतिक अस्पष्टता स्वयं पाकिस्तान के लिए एक संपत्ति हो सकती है, जो भारतीय योजनाकारों को बाहरी कूटनीतिक दबाव, खुफिया जानकारी साझा करने, हथियारों की आपूर्ति या यहाँ तक कि सीमित नौसैनिक समन्वय की संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर कर दे।

इस पैक्ट का समय भी महत्वपूर्ण है। ये वार्ताएँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रही हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के पास प्रतिरोध को अंतरराष्ट्रीय रूप देने का पूरा प्रोत्साहन है, केवल चीन के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रभावशाली मुस्लिम शक्तियों को साथ जोड़कर, जो एक कथानक गढ़ सकें और भारत के कूटनीतिक दायरे को जटिल बना दें। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहली त्रिपक्षीय नौसैनिक बैठक भी अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर में एक समुद्री आयाम जोड़ती है, ये क्षेत्र भारत के व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

पर भारत को ध्यान में रखना होगा कि यह नाटो नहीं है, और घबराहट से बचना होगा। इन तीनों देशों के हित अलग-अलग हैं, आंतरिक सीमाएँ हैं और कोई साझा कमांड संरचना नहीं है। फिर भी, प्रवृत्ति स्पष्ट है। भारत के लिए यह लाल बत्ती नहीं, बल्कि पीली बत्ती है, जो संकेत देती है कि पाकिस्तान के साथ भविष्य के संकट अधिक भीड़भाड़ वाले, अधिक राजनीतिक और तकनीकी रूप से अधिक जटिल रणनीतिक वातावरण में सामने आ सकते हैं।

एस.एम.एस. अस्पताल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अंतिम निर्णय में यह कहा कि अभ्यर्थी डॉक्टरी करने के लिए समर्थ नहीं है, और उसकी दिव्यांगता प्रतिशत अधिक है। यह मेडिकल रिपोर्ट एस.एम.एस. अस्पताल के डिसेबिलिटी मेडिकल बोर्ड द्वारा नीट यूजी के एडमिशन व काउंसलिंग बोर्ड को दी गई थी, जिसमें 23 सितम्बर, 2025 को रमन खण्डेलवाल की दावेदारी इस रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दी गई।

रमन खण्डेलवाल ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पुनः अपनी दिव्यांगता का प्रतिशत तय करने के लिए मेडिकल टैस्ट की गुहार की थी। उनका कहना था कि परीक्षा में भाग लेने से पूर्व उनकी दिव्यांगता, एक हाथ न होने की वजह से, 55 प्रतिशत आंकी गई थी, जो नियमानुसार उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हिमांशु जैन ने भी अदालत को सुनवाई के दौरान कहा था कि एस.एम.एस. अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट अवैज्ञानिक और अनियमित तरीके से बनाई जा रही है। अदालत ने 24 सितम्बर को ही पुनः मेडिकल जांच करने के आदेश दिए थे, परन्तु एस.एम.एस. के मेडिकल बोर्ड ने रमन खण्डेलवाल की "लोको मोटर डिसेबिलिटी" को अधिक बताते हुए उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया।

- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हिमांशु जैन ने भी अदालत को सुनवाई के दौरान कहा था कि एस.एम.एस. अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट अवैज्ञानिक और अनियमित तरीके से बनाई जा रही है।

तत्पश्चात रमन खण्डेलवाल ने हाई कोर्ट की खण्डपीठ के समक्ष अपील दायर की थी, जिसके आदेश अनुसार, दिल्ली सफदर जंग अस्पताल में डिसेबिलिटी मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी पुनः जांच की गई और 9 दिसम्बर, 2025 को जारी रिपोर्ट में उन्हें डाक्टरी पढ़ने और अभ्यास करने के लिए सक्षम पाया गया।

इस रिपोर्ट के आधार पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश मिश्रा और संगीता शर्मा ने 19 दिसम्बर को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को डॉक्टरी पढ़ने और नीट यूजी में उत्तीर्ण होने के बाद मैडिकल कॉलेज में दाखिला देने से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही, अदालत ने हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उपयुक्त पाया।

ह